THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) During his official visit to Germany from February 2-5, 1994, Prime Minister met representatives of German Business and Industry with a view to invite them to look at India as a trade and investment partner and generate increased interest among potential investors. Receipt and consideration of proposals from German investors is a continuing process. Approvals have already been accorded to 205 proposals for foreign direct investment by German firms in Indian companies in the post policy period i.e. from Aogust, 1991 to March, 1994 involving froeign investment of Rs. 339.09 crores. 15 proposals of foreign direct investment approved during February-March, 1994 envisaging investment by German companies is of the order of Rs. 52.2 crores in sectors such as metallurgical industry, industrial machinery, prime movers, polymer based products, homoepathic and herbal medicines, leather wallets, air brake systems for railway vehicles, computer software, electric power tools and trading.

Indian Leather Industry

5916. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian leather industry has the advantage of good quality raw materail, cheap labour and skilled craftsmen;

(b) whether it is also a fact that inspite of these advantages there is delay in delivery of orders, lack of proper quantity control, inadequate investment in latest technology; and

(c) if so, the steps being taken to remove these handicaps and boost the industry;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

(b) These drawbacks do not hold good for the entire industry.

(c) The Government launched in the year 1992, a Programme—National Leather Development Programme—with a view to strengthen the institutional support for the industry in the areas of Human Resources Development, Design & Product Development, Testing & Quality Control, enhanced export capability, Developing Supporting infrastructure and Systems of Coordination.

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के साथ भारत में निवेश के संबंध में बातचीत

5917. **श्री अजीत जोगी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार तथा ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के बीच ब्रिटेन द्वारा भारत में पूंजी निवेश करने के संबंध में हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त बातचीत के परिणामस्वरूप स्वीकृत किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत में ब्रिटेन से और अधिक पूंजी निवेश आकृष्ट करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारत में ज्यादा निवेश पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को आमंत्रित किया गया था। ब्रिटिश प्रधान मंत्री को सूचित किया कि वह भारतीय व्यापार तथा निवेश बाजार की मुक्तता के बारे में ब्रिटिश व्यापारियों को बतायेंगे और ब्रिटेन द्वारा अधिक पूंजी निवेश करने को कहेंगे।

(ख) क्योंकि इस प्रकार के पूंजी निवेश के निर्णयों के फलीभूत होने में समय लगता है तथा प्रधान मंत्री के स्तर पर हुई बातचीत सामान्य है विशेष नहीं।

(ग) ब्रिटेन द्वारा भारत में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इनमें भारतीय आर्थिक नीतियों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार ब्रोशरों तथा फ्लॉपी डिस्केट्स, विडियो कैसेट्स आदि द्वारा करना, संगोष्ठियों तथा निवेश संवर्धन प्रतिनिधि मंडलों आदि का आयोजन करना इत्यादि शामिल है। ब्रिटिश उद्योग में भारत का प्रचार करने और अधिक पूंजी निवेश खासतौर से वहां के लघु तथा मंझौले उद्योग से पूंजी निवेश आकृष्ट करने के उद्देश्य से भारत-ब्रिटिश भागीदारी उपायों को दूसरे वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

मधुमक्खी पालन-उद्योग में संकट

5918. **श्री अजीत जोगी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में मधुमक्खी पालन-उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ग) इन परिवारों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) मधुमक्खी पालन-उद्योग को बचाने के लिए प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। थाई साक बूड बायरस रोग के कारण, केरल और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में मधुमक्खी पालन उद्योग अत्याधिक प्रभावित हुआ है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के दायरे में आने वाले परिवारों में से 29,252 मधुमक्खी पालक जिनके पास 2,42,541 कालोनियां है, प्रभावित हुए हैं।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने 2 करोड़ रुपये आवंटन करके पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया है और केरल तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में मधुमक्खी पालकों की पुनर्स्थापना के लिए 50 लाख रुपये तदर्थ अनुदान के रूप में पहले ही मंजूर कर दिये हैं। राज्य निदेशक, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग तिरुवंतपुरम को मधुमक्खी नर्सरियां स्थापित करने के लिए पहले ही 34.88 लाख रुपये जारी कर दिये गये हैं। बीमारी के कारण हुए नुकसान का मूल्यांकन करने और पुनर्वास कार्यक्रम की मानीटरी करने तथा इसकी प्रगति पर नजर रखने के लिए एक मानीटरिंग समीक्षा समिति का भी गठन किया गया है।

(घ) मधुमक्खी कालोनियों की संपूर्ण बरबादी को रोकने के लिए एहतियाती उपाय करने और मधुमक्खी पालकों को उक्त रोग की जानकारी कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा शिविर आयोजित किये गये हैं। नुकसान का अंदाजा लगाने, पुनर्स्थापना योजनाएं तैयार करने और प्रगति की मानीटरी करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया है। अधिक शहद बनाने वाली "एपिस मेलीफेरा" जाति की मधुमक्खी की शुरूआत करने और संवर्धन, वृद्धि करने के लिए रोग प्रतिरोधी "एपिस सेरेना" मधुमक्खी का चयन करने तथा इन्हें मधुमक्खी पालकों को देने के लिए 24 मधुमक्खी पालन केन्द्र की स्थापना करने के लिए 34.88 लाख रुपये जारी किये गये हैं। पुनर्स्थापना प्रक्रिया को तेज करने के लिए सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं।